



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939

No. 2842]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVINA 13, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(मसाला बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3244(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मसाला बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) को सहायता अनुदान प्रदान करके 'केंद्रीय क्षेत्र स्कीम' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) निम्नलिखित को प्रशासित करता है:—

मसाला निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता सुधार हेतु एकीकृत स्कीम और इलायची अनुसंधान एवं विकास;

और, उपरोक्त स्कीम मौजूदा स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्कीम के विभिन्न उपसंघटकों के अधीन खेती के उपकरण, बीज, पौधे खरीदने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, खेती उत्पादन के प्रसंस्करण तथा श्रमिकों के बच्चों के लिए फीस के नकद भुगतान, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार; और मसाला उपजकर्ताओं, कृषकों, श्रमिकों, श्रमिकों के बच्चों तथा व्यष्टिक निर्यातकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा गया है) को कीट नियंत्रण कीटों, चिकित्सा फायदे, प्रक्षेत्रों का कार्बनिक प्रमाणन, मृदा विश्लेषण एवं प्रशिक्षण (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से फायदा कहा गया है) के रूप में सहायता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वधित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016) (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है; अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करें या अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।
- (2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नामांकन कराने हेतु आवेदन करना होगा, और यदि, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति अपना आधार नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर सूची उपलब्ध है, वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर जा सकते हैं।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन कराने की सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में, जहां उनके ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो वहां विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसके आधार नामांकन की आई डी स्लिप; या
- (ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
- (ii) मतदाता पहचान पत्र, या
- (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iv) पासपोर्ट; या
- (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (vi) राशनकार्ड; या
- (vii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या
- (viii) किसान फोटो पासबुक; या
- (ix) ऐसे व्यक्ति की फोटो सहित पहचान पत्र जिसे राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया गया हो; या
- (x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेज विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:

- (1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही इस स्कीम के अधीन नामांकन न करा पाए हों तो विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार

नामांकन के लिए अपने अनुरोध कार्यान्वयन एजेंसी के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएंगे।

- (3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. 3/1012/2015 बागान (समन्वय)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SPICES BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

S.O. 3244(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Commerce (*hereinafter referred to as the Department*) under the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India is administering the following Central Sector Scheme (*hereinafter referred to as the Scheme*) by providing Grant-in-Aids to the Spices Board (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) for the implementation of the Scheme:

Integrated Scheme for Export promotion and quality improvement in spices and Research and Development of Cardamom;

And whereas, the aforesaid Scheme provide subsidy for buying farming equipment, seeds, plants, technology upgradation, processing of farming output and cash payment towards fees for labourers children, scholarships and awards; and in-kind assistance in the form of pest control kits, medical benefits, organic certification of farm, soil analysis, and training (*hereinafter collectively referred to as the benefits*) to the spice growers, farmers, labourers, children of labourers and the individual exporters (*hereinafter collectively referred to as the beneficiaries*) under various sub-components of the Scheme as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involve expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Schemes shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any Individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st December, 2017, and in case, he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing

Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department through its implementing agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st December, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1012/2015-Plant (coord)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

(रबड़ बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3245(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) देश भर में रबड़ उद्योग के सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य से 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का दीर्घकालिक एवं समावेशी विकास' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम के अधीन रबड़ बोर्ड को सहायता अनुदान प्रदान कर रही है;

और यह विभाग इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु रबड़ बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) को सहायता अनुदान प्रदान करता है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्कीम के विभिन्न उप घटकों के अधीन रबड़ उपजकर्ताओं, श्रमिकों, श्रमिकों के बच्चों, व्यष्टिक डीलरों एवं व्यष्टिक निर्यातकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायिकी एवं छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) प्रदान करता है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्बधित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है; अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, उसे 31 दिसंबर, 2017 तक, आधार नामांकन कराने हेतु आवेदन करना होगा, और यदि, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु हकदार है, तो ऐसे व्यष्टि अपना आधार नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर सूची उपलब्ध है, वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन कराने की सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में, जहां उनके ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो वहां विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

परन्तु ऐसे व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसके आधार पंजीकरण की आई डी स्लिप; या
- (ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा पोस्ट आफिस पासबुक; या
- (ii) मतदाता पहचान पत्र, या
- (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iv) पासपोर्ट; या
- (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (vi) राशनकार्ड; या
- (vii) एमजीएनआरआईएस कार्ड; या
- (viii) किसान फोटो पासबुक; या
- (ix) उस व्यक्ति की फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र जिसे राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया गया हो; या
- (x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेज विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही इस स्कीम के अधीन नामांकन न करा पाए हों तो विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध कार्यान्वयन एजेंसी के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएंगे।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. 3/1012/2015 बागान (समन्वय)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

(RUBBER BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

S.O. 3245(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Commerce (hereinafter referred to as the Department) under the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India is providing Grants-in-Aid to the Rubber Board under the Central Sector Scheme of "Sustainable and Inclusive Development of Natural Rubber Sector" (*hereinafter referred to as the Scheme*) with the key objective of overall development of the rubber industry across the country;

And whereas, the Department provides Grants-in-Aid to the Rubber Board (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) for implementing the Scheme, which, *inter-alia*, provides subsidies and scholarships (*hereinafter referred to as the benefits*) to the rubber growers, workers, children of the workers, individuals dealers and the individual exporters (*hereinafter together referred to as the beneficiaries*) under various sub-components of the Scheme as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of receiving the benefits under the Scheme who does not possess the Aadhaar number or, who has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment by 31st December, 2017, and in case, he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre

[list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled for Aadhaar, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any one of the following documents:-
 - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (ii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (iii) Certificate of identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an Official Letter Head; or
 - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or
 - (v) Passport; or
 - (vi) Ration Card; or
 - (vii) Bank Passbook or Post Officer Passbook with photo; or
 - (viii) any other document specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by Department through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

- (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Scheme and, in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar Enrolment Centre available in their areas by 31st December, 2017 and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (2) in case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of the enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may register their requests for enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1012/2015-Plant(Coord)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

(कॉफी बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3246(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) देश भर में कॉफी उद्योग के सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य से 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केन्द्रीय स्कीम के अधीन कॉफी बोर्ड को सहायता अनुदान और सहायिकियाँ प्रदान करता है;

और, स्कीम के अधीन कॉफी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) को दी जाने वाली सहायता अनुदान का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा स्कीम के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार स्कीम के विभिन्न उप घटकों के अधीन कॉफी उपजकर्ताओं, कामगारों के बच्चों अथवा लघु कॉफी उपजकर्ताओं तथा व्यष्टिक निर्यातकों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को सहायिकियों और छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करता है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्बधित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है; अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं कराया है, उसे 31 दिसंबर, 2017 तक, आधार नामांकन कराने हेतु आवेदन करना होगा, और यदि, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति अपना आधार नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर सूची उपलब्ध है, वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन कराने की सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में, जहां संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो वहां विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

परन्तु ऐसे व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसके आधार नामांकन की आई डी स्लिप; या
- (ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (i) मतदाता पहचान पत्र, या
- (ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

- (iii) उस व्यक्ति की फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र जिसे किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया गया हो; या
- (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (v) पासपोर्ट; या
- (vi) राशनकार्ड; या
- (vii) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा पोस्ट आफिस पासबुक; या
- (viii) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; या
- (ix) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या
- (x) किसान फोटो पासबुक;

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेज विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा, अर्थात्:

- (1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही इस स्कीम के अधीन नामांकन न करा पाए हों तो विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध कार्यान्वयन एजेंसी के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएंगे।
- (3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. 3/1012/2015 बागान (समन्वय)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

(COFFEE BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

S.O. 3246(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Commerce (*hereinafter referred to as the Department*) under the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India is providing Grants-in-Aid and subsidies to the Coffee Board under the Central Sector Scheme of "Integrated Coffee Development Project" (*hereinafter referred to as the Scheme*) with the key objective of overall development of the coffee industry across the country;

And whereas, the Grants-in-Aid given to the Coffee Board (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) under the Scheme, *inter-alia*, is used for giving subsidies and scholarships (*hereinafter referred to as the benefits*) to the coffee growers, children of the workers or tiny coffee growers and the individual exporters (*hereinafter together referred to as the beneficiaries*) under various

sub-components of the Scheme as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of receiving the benefits under the Scheme who does not possess the Aadhaar number or, who has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment by 31st December, 2017, and in case, he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (b) (i) If he or she has enrolled for Aadhaar, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any one of the following documents:-
 - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (ii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (iii) Certificate of identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an Official Letter Head; or
 - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or
 - (v) Passport; or
 - (vi) Ration Card; or
 - (vii) Bank Passbook or Post Officer Passbook with photo; or
 - (viii) any other document specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by Department through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Scheme and, in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar Enrolment Centre available in their areas by 31st December, 2017 and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

- (2) in case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of the enrolment centres within their vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may register their requests for enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1012/2015-Plant(Coord)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

(चाय बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3247(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु चाय बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) को सहायता अनुदान प्रदान करके "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय स्कीम को प्रशासित कर रहा है। स्कीम निम्नलिखित उप घटक से मिलकर बना है :—

- (i) चाय बागान विकास;
- (ii) अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन हेतु प्रोत्साहन सहित गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण
- (iii) बाजार संवर्धन - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय;
- (iv) अनुसंधान और विकास;
- (v) मानव संसाधन विकास; और
- (vi) राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम;

और, वर्तमान स्कीम मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्कीम के विभिन्न उपघटकों के अधीन उपर्युक्त स्कीम चाय उपजकर्ताओं, श्रमिकों, श्रमिकों के बच्चों और व्यष्टिक निर्यातकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को सहायिकी और सहायता अनुदान प्रदान (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से फायदा कहा गया है) करती है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्बधित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है; अर्थात : -

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।
- (2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं कराया है, उसे 31 दिसंबर, 2017 तक, आधार नामांकन कराने हेतु आवेदन करना होगा, और यदि, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु

हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति अपना आधार नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर सूची उपलब्ध है, वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन कराने की सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में, जहां संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो वहां विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

परन्तु ऐसे व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्:

- (क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसके आधार नामांकन की आई डी स्लिप; या
- (ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
- (ii) मतदाता पहचान पत्र, या
- (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iv) पासपोर्ट; या
- (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन जारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (vi) राशनकार्ड; या
- (vii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या
- (viii) किसान फोटो पासबुक; या
- (ix) उस व्यक्ति की फोटो सहित पहचान पत्र जिसे राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया गया हो; या
- (x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेज विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यष्टिक सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही इस स्कीम के अधीन नामांकन न करा पाए हों तो विभाग अपना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध कार्यान्वयन एजेंसी के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएंगे।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. 3/1012/2015 बागान (समन्वय)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

(TEA BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2017

S.O. 3247(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Commerce (*hereinafter referred to as the Department*) under the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of "Tea Development and Promotion Scheme" (*hereinafter referred to as the Scheme*) by providing Grant-in-Aids to the Tea Board (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) for implementation of the Scheme. The Scheme consists of the following sub-components:

- (i) Tea Plantation Development;
- (ii) Quality Up-gradation and Product Diversification including incentive for Orthodox tea production;
- (iii) Market Promotion – Domestic and International;
- (iv) Research and Development;
- (v) Human Resource Development; and
- (vi) National Programme for Tea Regulation;

And whereas, the aforesaid Scheme provides subsidy and Grant-in-Aid (*hereinafter collectively referred to as the benefits*) to the tea growers, labourers, children of labourers and the individual exporters (*hereinafter collectively referred to as the beneficiaries*) under various sub-components of the Scheme as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any Individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st December, 2017, and in case, he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (c) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(iii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (d) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department through its implementing agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st December, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1012/2015-Plant (coord)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.